इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

देश में बेरोजगारी

697. **प्रो० रामबक्ष सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है,

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है, और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत तक बेरोजगारी की समस्या का हल होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 1987-88 के दौरान 12 मिलियन बेरोजगारी सामान्य मुख्य स्तर (यूपीएस) (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार 1993-94 के दौरान घट कर 9 मिलियन रह गई है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार व गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वतः ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

अनुमान है कि यदि 2007 तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो रोजगार वृद्धि की दर 2.8 प्रतिशत वार्षिक रखनी होगी।

Guidelines for Wage Settlement

698. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the new guidelines issued to the Public Sector undertakings by the Department of Public Enterprises that wage settlement should now be for a period of ten years instead of the current practice of five years;

(b) if so, what are the details of the guidelines issued in this regard;

(c) whether the major central trade unions have opposed these guidelines; and

(d) if so, the details thereof and Government's response thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Yes, sir. The Justice Mohan Committee has recommended that pay package and perquisites for officers and non-unionised supervisors, should be revised every 10 years instead of 5 years as has been the practice so far. The Government in their guidelines for the policy to be adopted for the Sixth round of wage negotiations in the Public sector enterprises have stated that in the event of the Government accepting the above recommendations, the revision of wages of the workers should be effected once in 10 years in order to ensure uniformity.

(c) No representation has been received so far from any major central trade union opposing recommendation of the Mohan Committee.

(d) Does not arise.

National wage Structure for Workers in Sugar Industry

699. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up a sub committee for deciding the national wage structure for workers in the sugar industry;

(b) if so, the criteria for selecting the members of the said committee, and

(c) the names of the members along with their affiliation, if the committee is already constituted?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) The suggestion to set up a sub committee for deciding the national wage structure for sugar industry was made by some members in the meeting of the tripartite committee on sugar industry which was held on 18.1.99. The Government is yet to take a final decision on setting up such a sub committee.

(b) and (c) Do not arise as the committee has not been constituted.

बेरोजगारी की घटी हुई दर

700. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर कम हुई है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आंकड़ों के स्रोत क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०), नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य प्रमुख स्थिति के अनुसार 1987-88 से 1993-94 तक की पांच वर्षों की अवधि में बेरोजगारी दर में कमी आई है। बेरोजगारी दर 1987-88 के दौरान 3.77 प्रतिशत एवं 1993-94 के दौरान 2.56 प्रतिशत थी।

(ग) नौवीं योजना में अल्प रोजगार की उच्च दर, श्रमिकों की बढ़ती नैमित्तिकता एवं गरीब लोगों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। अतः नौवीं योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना को कार्यान्वित करने पर बल दिया जाएगा।

बेरोजगार व्यक्ति

701. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से सरकार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करती है,

(ख) वर्तमान में बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान तैयार करने के लिए सूचना का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किया जाने वाला पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।

(ख) 1993-94 (एनएसएसओ का 50वां चक्र) में बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना हैं।

गरीबी उपशमन एवं रोजगार सृजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण पर हाशिम समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है एवं एनआरवाई, पीएमआईयूपीईपी तथा यूबीएसपी (गरीब लोगों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं) को चरणबद्ध कर दिया गया है। योजना पर 1.12.1997 से कार्य शुरू कर दिया गया है। एसजेएसआरवाई शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीब लोगों को स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं मजदूरी नियोजन के माध्यम से उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने पर बल देती है।

ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना को एक केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

राज्य-वार बेरोजगारी (000 व्यक्ति) (यू०पी०एस०)*

क्र०सं०	राज्य	बेरोजगारी 1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	454
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	590